अमृत वाणी

लोगों को प्रकाश दो, वे अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेगें।

– कार्ल मैक्सी

संपादकीय

माओवादियों पर वर्ष का अंतिम निर्णायक प्रहार

सुरक्षाबलों ने तय लक्ष्य के अनुसार माओवादियों पर अपना अंतिम निर्णायक प्रहार कर दिया और उसके साथ ही छह माह पूर्व किए गए कुख्यात नक्सली कमांडर वासवराजू और उसके पश्चात खूंखार माओवादी सरगना हिड़मा के खात्मे के बाद अब 24 दिसंबर को ओड़ीसा के कंधमाल के जंगलों में हुए एक भीषण मुठभेड़ में माओवादियों के एक और शीर्ष नेता उनकी केन्द्रीय समिति के सदस्य एक करोड़ के इनामी दुर्दान्त माओवादी गणेश उइके को मार गिराने में सफलता हासिल कर ली। इसके साथ ही माओवादी संगठन की कमर पूरी तरह से टूट गई है। उसके तीन तीन शीर्ष नेता वासवराजू, हिड़मा और अब गणेश उइके के मारे जाने से माओवादी संगठन का शीर्ष नेतृत्व ही खत्म हो गया है।

गणेश उइके माओवादी संगठन का थिंक टैंक माना जाता रहा है। वह केन्द्रीय समिति का सबसे प्रभावशाली सदस्य था। बताया गया है कि हिड़मा की मौत के बाद वह दण्डकारण्य क्षेत्र और बस्तर डिवीजन का मुखिया था जो छत्तीसगढ़ ओड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में नक्सली नेटवर्क को संचालित करता था। अत: उसकी मौत से पूरे माओवादी संगठन में खलबली मच जाना स्वाभाविक है।

इधर डीआइजी ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह ने सुरक्षाबलों की इस विशाल उपलब्धि के लिए उनके आपसी तालमेल और साहसिकता की सराहना की है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश को पूरी तरह नक्सली समस्या से मुक्त करने के लिए मार्च 2026 की तारीख तय की है और यह कहना गलत नही होगा कि सुरक्षाबलों व्दारा माओवादी संगठन को नेतृत्व विहीन कर देने की विशाल उपलब्धि ने उस लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग आसान कर दिया है। जैसे जैसे यह नियत तिथि करीब आ रही है सुरक्षा बलों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं और माओवादियों पर उनका दहशत कायम होता जा रहा है। अब वह दिन दूर नही जब बचे कुचे संगठन से जुड़े छोटे मोटे माओवादी भी हथियार डालने आगे आ जाएगें क्योंकि उन्हें अब तक यह बात तो भलीभांति समझ में आ गई होगी कि उनके लिए बचाव का एक मात्र मार्ग मुख्यधारा से जुड़ जाना ही शेष है। इससे जान तो बचेगी ही शासन की पुनर्वास नीति के सहारे एक नया जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। अगर फिर भी कोई संगठन के प्रति मोह पालने की कोशिश करता है तो उनका या तो सुरक्षा बलों के हाथों जेल जाना तय है अथवा मौत को गले लगाना।

देश को नक्सली आतंक से मुक्त करने की दिशा में अगर केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की नीति कारगर रही है तो यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए कि उसे अंजाम देने का पूरा पूरा श्रेय हमारे साहसी और शक्तिशाली सुरक्षा बलों को ही जाता है। इस सफलता के सोपान पर कदम रखने के लिए उन्हें भी बहुत कीमत चुकानी पड़ी है, बहुत त्याग करने पड़े है लेकिन आज वह दिन बहुत करीब आ गया है जब अपने और अपने सारे साथियों के मूल्यवान योगदान और त्याग को सार्थक कर सकेगें। सर्वोपरि बस्तर एवं सभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों के निवासियों को एक हिंसामुक्त माहौल देकर उनके चेहरों पर सुकून भरा मुस्कान ला सकेगें।

भारत के नए मुक्त व्यापार समझौते से खेत से लेकर कारखाने तक रोजगार और समृद्धि बढ़ेगी

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम को प्रतिबिंबित करता है - यह रोजगार सृजन को तेज करता है, निवेश को बढ़ावा देता है और भारत के छोटे व्यवसायों, छात्रों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए परिवर्तनकारी अवसरों के द्वार खोलता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित यह समझौता, मोदी सरकार किया गया सातवां एफटीए है और 2025 का तीसरा प्रमुख व्यापार समझौता है, जो ब्रिटेन और ओमान के साथ हुए ऐतिहासिक, लाभकारी समझौतों के बाद हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी एफटीए विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से काफी अधिक है। यह एफटीए वैश्विक व्यापार वार्ताओं में भारत की बढ़ती शक्ति और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है। प्रत्येक समझौते पर सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद वार्ता की गई है, जिससे संतुलित परिणाम सामने आये हैं और विकसित दुनिया के साथ वास्तविक लाभकारी सहभागिता सुनिश्चित हुई है।

इस एफटीए का एक केंद्रीय स्तंभ रोजगार सृजन है। न्यूजीलैंड भारतीय निर्यात की शत-प्रतिशत पहुंच के लिए शून्य-शुल्क की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भारत के श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, परिधान, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग वस्तुओं को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा लाभ भारतीय श्रमिकों, कारीगरों, महिला उद्यमियों, युवाओं और एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा।

भारत ने अपनी बाजार पहुँच और सेवाओं की पेशकश को भी सुरक्षित किया है, जिसमें दूरसंचार, निर्माण, आईटी, वित्तीय सेवाएं, यात्रा और पर्यटन समेत 118 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह विस्तारित पहुंच, भारतीय पेशेवरों और व्यवसायों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

इस समझौते में भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए प्रवेश और रहने के बेहतर प्रावधान हैं। यह समझौता अध्ययन के दौरान काम करने के अवसर, अध्ययन के बाद रोजगार और एक सुव्यवस्थित कार्य-अवकाश (वर्किंग-हॉलिडे) वीज़ा व्यवस्था को सक्षम बनाता है।

एसटीईएम स्नातक और परास्नातक अब तीन वर्षों तक काम कर सकते हैं, जबकि डॉक्टरेट शोधकर्ता चार वर्षों तक काम कर सकते हैं, जिससे भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व वैश्विक अनुभव और कैरियर के मार्ग खुलते हैं। एक नया अस्थायी रोजगार प्रवेश वीज़ा उन कुशल भारतीय पेशेवरों का समर्थन करता है, जो अंतरराष्ट्रीय अवसरों की तलाश में हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का विज़न स्पष्ट हैः भारतीय किसानों को वैश्विक मंच पर सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। एफटीए इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

इस समझौते के तहत सेब, कीवी और शहद को शामिल करते हुए एक कृषि उत्पादन साझेदारी स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है। न्यूजीलैंड ने बासमती चावल के लिए जीआई स्तर सुरक्षा देने की भी प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारतीय चावल किसानों को मजबूत समर्थन मिलेगा।

महत्वपूर्ण रूप से, भारत ने सुनिश्चित किया है कि चावल, डेयरी, गेहूं, सोया और अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहें और किसी भी बाज़ार के खुलने से घरेलू आजीविका को कोई नुकसान ना पहुंचे।

भारत के एफटीए आज सिर्फ शुल्क-कटौती से कहीं आगे बढ़ गये हैं। ये एफटीए किसान, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर खोलने के उपाय हैं, साथ ही ये राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा भी करते हैं।

विभिन्न व्यापार समझौतों से भारतीय निर्यात तत्काल या तेज शुल्क उन्मूलन के जरिये लाभान्वित होता है, जबकि भारत के अपने बाजार का खुलना सोच-समझकर और धीरे-धीरे हो रहा है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जो भारत के ईएफटीए देशों - स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन - के साथ हुए एफटीए के निवेश से जुड़े अभिनव प्रावधानों को दर्शाता है।

न्यूजीलैंड के लिए, यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक बड़े छलांग का प्रतीक है। पिछले 25 वर्षों में, न्यूजीलैंड ने भारत में लगभग 643 करोड़ रुपये का निवेश किया है। नई प्रतिबद्धता - अगले 15 वर्षों में लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये - एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें निवेश लक्ष्यों को पूरा न करने पर दुबारा पूरा करने की व्यवस्था का प्रावधान है।

इस निवेश का अधिकांश हिस्सा कृषि, डेयरी, एमएसएमई, शिक्षा, खेल और युवाओं के विकास का समर्थन करेगा, जिससे व्यापक और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

यह समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि हैः यह भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला एफटीए है। वार्ता करने वाली पूरी टीम के सदस्यों में - मुख्य वार्ताकार और उपमुख्य वार्ताकार से लेकर वस्तु, सेवा, निवेश की प्रतिनिधि और न्यूजीलैंड में हमारी राजदूत तक - अधिकाँश महिलायें थीं। हमारी सक्षम महिलाएं प्रधानमंत्री के विकास एजेंडा में नेतृत्व भूमिका निभाने लगी हैं। भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भारत की स्पष्ट रणनीति का उदाहरण हैः विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी करना, जो भारतीय उत्पादों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा किए बिना भारत के श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए अपने बाजार खोलती हैं।

मोदी सरकार के तहत हुए व्यापार समझौते मात्र लेन-देन नहीं हैं–ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारतीयों, विशेषकर सबसे गरीब लोगों, के जीवन को बेहतर बनाने के व्यापक मिशन का हिस्सा हैं। इस रणनीति ने भारत के 2014 के च्कमजोर पांचज् में से एक होने की स्थिति को बदल दिया है, अब देश वैश्विक विकास का इंजन और वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश का पसंदीदा साझेदार बन गया है।

आज भारत आत्मविश्वास और ताकत के साथ वार्ता करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कृषि, डेयरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहें और समझौते केवल तभी किए जाएं, जब वे पारस्परिक लाभ प्रदान करते हों।

भारत का वर्तमान दृष्टिकोण अतीत की तुलना में बहुत अलग है। पहले की व्यापारिक नीतियाँ अक्सर पर्याप्त परामर्श के बिना, भारतीय बाजारों को सस्ते आयात के जोखिम में डाल देती थीं तथा छोटे व्यवसायों और नौकरियों को खतरे में डालती थीं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और वार्ता शक्ति को बहाल किया है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिसे भारतीय उद्योग जगत में सराहना मिली है, 2014 के बाद शासन में हुए इस ताजगी भरे बदलाव का परिणाम है।

वस्तु, सेवा, निवेश और गतिशीलता को एकीकृत करके और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए, यह समझौता भारत की आधुनिक, समावेशी और संतुलित व्यापार कूटनीति को प्रतिबिंबित करता है। जैसे-जैसे भारत और न्यूजीलैंड आर्थिक एकीकरण को मजबूत कर रहे हैं, यह एफटीए दिखाता है कि व्यापार कैसे बाजार को खोल सकता है और सीमाओं के पार मानव-केंद्रित विकास और साझा समृद्धि प्रदान कर सकता है।

पीयूष गोयल
(ये लेखक के अपने विचार है)

जब गांधी घर में महकेगी देशी व्यंजनों की खुशबू

भोपाल में आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय गांधी जैविक उत्सव में विचार मंथन के फलस्वरुप समूचे देश के गांव में महात्मा गांधी जी की अवधारणा के अनुरूप गांधी घर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पत्थरों मिट्टी और काठ सहित स्थानीय सामग्री से देशज वास्तु के अनुरूप निर्मित इन घरों में किफायती दरों पर ठहरने के साथ ही आंचलिक व्यंजनों को परोसा जाएगा और अतिथियों को समृद्ध ग्रामीण परंपराओं हस्तशिल्प और कला साहित्य की जानकारी दी जाएगी इससे न सिर्फ ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर आर्थिकी , कला कौशल और आत्म सम्मान के पाए मजबूत होंगे । गांधी भवन में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय जैविक उत्सव के समापन दिवस पर विचार सत्र के दरम्यान डॉ. सुधीर सक्सेना,राजेश बादल , जे पी दीवान और परीक्षित सिंह के बीच गहन विचार मंथन के फलस्वरुप उक्त फ़लश्रुति सामने आई। गांधी भवन के मुक्ताकाशी सभागार में इस शानदार कामयाबी के बाद हर महीने जैविक उत्सव करने का फ़ैसला भी किया गया है ।

मध्य भारत के सबसे बड़े गांधी भवन में तीन दिवसीय राष्ट्रीय गांधी जैविक उत्सव का गुरूवार को भव्य समापन हुआ।इसमें क़रीब आधा दर्ज़न प्रदेशों के स्वयंसेवी संगठनों, किसानों,जैविक विशेषज्ञों, पत्रकारों,लेखकों और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया।भारत का यह पहला जैविक उत्सव था,जिसमें लगभग 30 जैविक स्टाल के प्रतिनिधियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। स्टाल का कोई शुल्क भी नहीं लिया गया। इसके अलावा यह पहली बार हुआ,जब उत्सव में किसानों की बची हुई सामग्री को भी गांधीभवन ने ख़रीद लिया। इससे उन्हें कोई घाटा नहीं हुआ।आयोजन में छह विमर्श सत्र हुए। इनमें निर्णय लिया गया कि हर महीने एक दिन का जैविक उत्सव गांधी भवन में होगा।गांधी भवन परिसर में एक गांधी घर भी बनाया जाएगा। इसमें अन्य अतिथियों के अलावा किसान बिना कोई शुल्क दिए ठहर सकेंगे। इस गांधी घर का निर्माण मिट्टी ,गोबर,भूसा और चूने से किया जाएगा। भवन में शीघ्र ही सौर ऊर्जा संचालित बिजली बनने लगेगी।

उत्सव में प्रतिदिन दो वैचारिक सत्र हुए।इनमें जैविक खेती से लाभ ,उर्वरकों के प्रयोग से नुक़सान,किचिन गार्डन ,रूफ गार्डन,पर्यावरण संतुलन , स्वच्छ पानी की उपलब्धता ,पर्यावरणीय पर्यटन, प्राकृतिक,परंपरागत और जैविक खेती की व्याख्या तथा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर गहन मंथन हुआ। इन सत्रों में हुए विमर्श का निचोड़ एक दस्तावेज़ की शक्ल में शीघ्र ही लोकार्पित किया जाएगा।

डॉक्टर सुधीर सक्सेना
(ये लेखक के अपने विचार है)

भारतीय व्यापारियों को वैकल्पिक बाजार ढूंढने चाहिए

भारतीय अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने व्यापार समझौते का संशोधित ऑफर अमेरिका को दिया है। इसे अमेरिका ने अब तक का बेस्ट ऑफर माना है। लेकिन उसकी निगाह में वह काफी नहीं है। वह अभी और रियायतें झटकने पर अड़ा हुआ है।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर ने वहां की संसद में कहा कि भारत ने ट्रेड डील के लिए अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। ये बयान लगभग उसी समय आया, जब द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता के लिए उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्वित्जर के नेतृत्व में अमेरिकी दल नई दिल्ली आया हुआ था। ग्रीयर के बयान से कुछ हलकों में उम्मीद जगी कि अब आखिरकार व्यापार समझौते पर सहमति बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने समझौते का संशोधित ऑफर अमेरिका को दिया है। इसके बावजूद भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने संकेत दिया है कि मार्च से पहले समझौते की संभावना नहीं है। स्पष्ट है, जिसे खुद अमेरिका ने भी बेस्ट ऑफर माना है, उसकी निगाह में वह काफी नहीं है। वह भारत से अभी और रियायतें झटकने पर अड़ा हुआ है। खबरों के मुताबिक भारत ने अमेरिकी बादाम, अखरोट, सेब, औद्योगिक उत्पादों, लग्जरी मोटरसाइकिलों आदि पर आयात शुल्क पूरी तरह हटाने की पेशकश की है। इसके बदले भारत ने सिर्फ यह मांग की है कि ट्रंप प्रशासन वो 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ हटा ले, जो रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर उसने लगाया है। अधिकारियों के मुताबिक अगर इस पेशकश पर भी समझौता हो जाता है, तो भारतीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता की अमेरिका इस पर राजी है। वह संभवतः भारत के पूरे कृषि एवं डेयरी बाजार को अपने उत्पादों के लिए खुलवाने से कम किसी बात पर सहमत नहीं है। अमेरिकी अधिकारी बेलाग कहते सुने गए हैं कि चीन के अमेरिकी कृषि पैदावार की खरीदारी सीमित करने से जो समस्या उनके सामने आई है, ट्रंप प्रशासन भारतीय बाजार खुलवा कर उसका समाधान निकालना चाहता है। क्या भारत इसके लिए राजी होगा?

वर्ग पहेली 5957

संकेतः बाएं से दाएं

1. 4 मई 1979 को श्रीमती मार्गरैट थैचर इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी (3)
4. महाकवि कालीदास की सप्रसिद्ध कृति (4)
7. जल से उत्पन्न (3)
8. अभ्यास पुस्तिका को अंग्रेजी में यह कहते है (4)
11. पंचतत्वों में से एक, आकाश, गगन (2)
13. शाखायुक्त, टहनीदार (4)
15. उत्तम, विशुद्ध, सदाशय (2)
16. बयाना, अग्रिम देय (3)
18. हानिकर या नाशक जीव या कीटाणु, चिपकाने की क्रिया (2)
19. जुड़वा, अश्विी कुमार (2)
21. दिशा में, पहलू (4)
23. हुनर, फन (2)
24. धर्मच्युत, पतित (2)
25. अधिकार, इख्तिहार (2)

ऊपर से नीचे

1. पुल को अंग्रेजी में यह कहते है (2)
2. दर्जी, वेशकार, सूचिक (3)
3. अरब का प्रसिद्ध नगर जहां हजरत अली कीमजार है (3)
5. अन्न, लकड़ी आदि में लगने एक प्रकार का छोटा कीड़ा (2)
6. एक प्रकार का कीट, पतंगा, परवाना (3)
9. यह हंगरी की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है (4)
10. कंगूरा, गुंबज, शिखर, घट (3)
11. पुरूष, मर्द (2)
12. जिसमें दाग या धब्बा लगा हो (2)
17. 4 मई 1902 को केसी रेड्डी का जन्म दिवस है जो इस प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे (4)
18. पृष्ठ, पन्ना (2)
20. मुझे (मराठी)(2)
21. तकलीफ, दर्द (2)
22. एक शब्द जिसके द्वारा वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी तीसरे मनुष्य का संकेत किया जाता है (2)

वर्ग पहेली 5956 का हल

इ	ज	रा	इ	ल		वि	श्व
रा	ज	न		व	की	ल	
व				इ	ना	य	त
ती	ज			न		न	ल
	न		आ	शि	क		वा
	वा	दा		म	श	हू	र
मौ	सा		बा	ला		र	
का		का	जू		हां		

सुडोकू पहेली क्रमांक- 5957

2	3				7			1
1	8		5	3		4		
	4	6						
	5				8			2
	6			2			9	
9			3					
						8	2	
		3		5	9		4	7
5			7				3	9

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक हैं, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी व खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सुडोकू पहेली क्र. 5956

6	4	7	1	9	3	2	8	5
9	5	2	6	8	7	1	4	3
3	1	8	2	4	5	9	6	7
4	3	6	5	2	9	7	1	8
5	8	9	7	1	6	3	2	4
2	7	1	4	3	8	5	9	6
8	2	5	3	6	1	4	7	9
7	9	4	8	5	2	6	3	1
1	6	3	9	7	4	8	5	2